श्री भगवत झा आजाद : दूसरी भी पढ़ दूं ।

श्री सभापति : जी हां ।

Expenditure on Management of taken-over Sugar Factories

*47. SHRIMATI AMARJIT KAUR:
SHRI RAMANAND YADAV:†

Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) what is the total amount of money loaned or invested by the Central Government in the management of eight sugar factories taken-over by Government under the Temporary Taken-over of Sugar Undertaking Management Act, 1978; and

(b) what is amount of further loans being granted by Government to enable these factories to take up crushing operations of sugarcane during the season 1984-85 whether all these mills are running at a loss?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI BHAGWAT JHA AZAD): (a) The Central Government has given only loans to the eight sugar factories. The total amount of the loans is Rs. 24.0752 crores.

(b) Further loans have not so far been granted to these factories for cane crushing operations which are to commence for the sugar year 1984-85. Most of the mills are running at a loss mainly because they have been required to buy cane at uneconomic prices fixed under the advice of the various State Governments as well as the fact that a majority of these factories have old and outdated plant and equipment which has worked at a lower efficiency.

श्री वीरेन्द्र वर्मा : आप ने तो अलग-अलग ले लिया था ।

श्री रामानन्द यादव : मुझे कोई एतराज नहीं है, दोनों को मिला कर रखा जाये ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : मान्यवर, मंत्री जी खुद भी चाहते थे कि अलग-अलग लिया जाये ।

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Ramanand Yadav.

श्री सभापति : अब हो गया है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित । मान्यवर, उत्तर प्रदेश की अयोध्या शुगर फैक्ट्री पर 9 लाख 6 हजार रुपये अवशेष हैं 1977–78 का । उत्तर में दिया गया है दावेदारों के न मिलने के कारण लम्बित । तो जब दावेदार नहीं हैं और हैं केन ग्रोवर्स का तो क्या केन ग्रोवर्स के जनरल इन्टरेस्ट में सरकार इस राशि को खर्च करने पर विचार करेगी ?

सातवीं शुगर फैक्ट्री लक्सर उत्तर प्रदेश की है, जिस पर 13 लाख 83 हजार रुपया सन 78–79 का अवशेष है । लिखा है उत्तर प्रदेश की सरकार के फैसले की प्रतीक्षा में । तो सन् 78–79 का उत्तर प्रदेश की सरकार का कौन सा ऐसा फैसला है जिसकी अभी तक प्रतीक्षा हो रही है और उसके फैसला न देने के कारण किसानों का 13 लाख 83 हजार रुपया अवशेष है, जिस पर प्रकाश डालने की कृपा करें ।

श्री भगवत झा आजाद : सभापति महोदय, अयोध्या शुगर मिल पर जो 9 लाख 6 हजार रुपया बकाया है वह इसलिये नहीं है कि हम देना नहीं चाहते, हमारे पास रुपये हैं ।

श्री सभापति : वह तो लिखा हुआ है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : मंत्री जी ने कहा है कि 9 लाख 6 हजार रुपये इस लिये बकाया हैं क्योंकि दावेदार नहीं आते । तो मैंने यह पूछा है कि क्या मंत्री जी उस 9 लाख 6 हजार रुपये को जो किसानों का बकाया है उसे किसानों के इन्टरेस्ट में व्यय करने पर विचार करेंगे ?

श्री भगवत झा आजाद : सभापति महोदय, यह कहना मेरे लिये मुश्किल है कि मैं इस को खर्च करूं जनरल इन्टरेस्ट में क्योंकि दावेदार नहीं है । कुछ कारण

हो सकते हैं, अब और ताकत के साथ दावेदारों को खोजवाऊंगा । अगर बिल्कुल नहीं मिलेगें तो फिर आपने जो कहा है, वह सुझाव विचारणीय है । जो आपने लक्सर के बारे में कहा, उस संबंध में हाई कोर्ट में केस हो गया था और इस लिये लम्बित था ।

श्री सभापति : फैसला भी हो गया ।

श्री भगवत झा आजाद : अब कुछ पोइंट्स पर उत्तर प्रदेश सरकार को राय देनी है । हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी कराने के लिये और फिर लिखेंगे कि कृपया अपनी राय जल्दी दे दीजिये मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि 9 लाख और 13 लाख जो बकाया है, यह पैसा हमारे पास देने के लिये जमा है; हम देना चाहते हैं, कठिनाई लेने वालों की है ।

श्री वीरेंद्र वर्मा : मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित शुगर फैक्ट्री लक्सर पर किसानों का बकाया पैसा न अदा करने के कारण वह फैक्ट्री ली गई । तो क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उस समय किसानों का कितना रुपया बकाया था जब उसको टेकओवर किया और चीनी का स्टाक उस सेशन का कितना बाकी था ?

श्री भगवत झा आजाद : लक्सर फैक्ट्री ली गयी 2-2-79 को । उस समय कितना था यह हम नहीं कह सकते, क्षमा चाहता हूं, हमें नहीं ख्याल था कि आप इतना पीछे चले जायेंगे । अभी जो बाकी है वह हम दे देंगे । लक्सर का 78-79 में जो था उसके अनुसार 106 लाख था, यह 79-80 में कम करके हो गया 52 लाख, फिर 80-81 में 61 लाख और 81-82 में हो गया 60 लाख । अभी तत्काल क्या पोजीशन है यह नहीं बता सकता, आडिट हो रहा है, उसके बाद बता सकता हूं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : मान्यवर, मेरी जानकारी के अनुसार 50 लाख रुपया किसानों की देनदारी का बकाया था मिल पर जब गवर्नमेंट ने टेकओवर इस फैक्ट्री को किया ।

SHRI J. K. JAIN: Sir, I want to know as to how many supplementaries one Member can put.

MR. CHAIRMAN: This is the second supplementary.

SHRI J. K. JAIN: I have no objection if he is permitted second supplementary because he has already put two supplementaries. I have no objection if he is permitted three supplementaries. He has already put two. We just want a clarification from the Chair as to how many supplementaries are permitted now.

श्री उपसभापति : हर सप्लीमेंट्री के बच्चे भी शामिल रहते हैं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह मालूम कर रहा था कि जैसी कि उन्होंने फिगर्स दी कि 50 लाख रुपया उस समय देनदारी का था किसानों के गन्ने की कीमत का । मेरी जानकारी के अनुसार डेढ़ करोड़ रुपये की चीनी का स्टाक मिल में था । तो उस समय से अब क्या स्थिति है । उस समय डेढ़ करोड़ की चीनी थी और देनदारी थी 50 लाख की । पिछले 6 वर्षों में यह आपके नियन्त्रण में है । तो अब कितनी देनदारी है ? मान्यवर, इसमें लिखा है कि 1 करोड़ 59 लाख रुपये की फैक्ट्री की देनदारी बाकी है और चीनी का स्टाक उन्होंने कुछ बताया नहीं कि कितना है । इसी में यह भी पूंछ लूं कि ...]

श्री जे० के० जैन : दूसरा बच्चा हो गया अब ।

SHRIMATI MONIKA DAS: How many can he raise?

श्री वीरेन्द्र वर्मा : और कई भी बच्चे होंगे, बहिन जी, फिक्र न करो । ... (व्यवधान) । माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि चीनी की रिकवरी उस समय कम थी । केवल एक शुगर फैक्ट्री की ये बता दें कि 1978-79 में क्या थी

और जब से उन्होंने टेकओवर किया है तो अब चीनी की रिकवरी क्या है ?

श्री भगवत झा आजाद : मान्यवर, इनके तीन बच्चे जो सामने आये हैं उनमें पहले का मैं जवाब दे रहा हूं। 1978-79 का जो मैंने बताया वह 13.83 लाख था। वह इसलिये नहीं कि हम देने वाले नहीं है। आपने स्वयं अपने प्रश्न का जवाब दिया, कि 193.06 लाख टोटल एरियर है वर्तमान में। फाइनेंशल परफार्मेंस का मैंने कहा कि 1978-79 का घाटा 106 लाख है, 1979-80 में वह 52 लाख हो गया, 1980-81 में वह 61 लाख हो गया और 1981-82 में 60 लाख हो गया। अभी कितना शुगर फैक्ट्रीज के पास है वह मैं नहीं बता सकता हूं, उसके लिये समय चाहिये।

श्री रामानन्द यादव : मान्यवर, वर्मा जी लखनऊ के रहने वाले है, अभी उनके 4-5 और बच्चे हो जायेंगे . . .(व्यवधान)

श्री सभापति : आप सवाल पूंछिये।

श्री रामानन्द यादव : मान्यवर, सरकार के सामने इन चीनी मिलों को लेने का एक महान उद्देश्य था कि किसानों के बकाया पैसे दे दिये जायें निर्धारित समय के अन्दर नहीं देंगे तो टेकओवर हो जाएंगे। सरकार ने इन मिलों को इसी ख्याल से लिया कि किसानों का पैसा दे दिया जाय। सरकार ने यह सोचा कि वह सक्षम है, किसानों की बकाया दे देगी और आइंदा किसानों का बकाया नहीं रहेगा। लेकिन मंत्री जी के जवाब से यह स्पष्ट मालूम होता है कि और भी बकाया चला गया। सरकार ने किसानों का काफी पैसा बाकी रखा है और मिलों का अधिग्रहण इसलिये किया कि मिल मालिक किसानों को गन्ने का दाम नहीं दे पाये थे। यह भी सरकार ने सोचा था कि हम इनको नफे में चलायेंगे, प्राइवेट वाले घाटे में चलाते है, इसलिये पेमेंट नहीं कर पाते। लेकिन हालत वही है . . .

श्री सभापति : वही की वही सूरत है ?

श्री रामानन्द यादव : और भी जैक हो गया। मान्यवर, मेरी नालेज में 31 करोड़ रुपये इनवेस्ट किये है उन मिलों को लेने और चलाने के लिये, रिनोवेट करने के लिए, पुनः कार्यरत करने के लिये सरकार ने। लेकिन यह कह रहे है 24 करोड़। मेरी अपनी जो इन्फारमेशन है, पिछले एक प्रश्न के उत्तर में शायद इन्होंने ही कहा था कि 31 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हो चुका है। आठों को चलाने के लिये सब को प्रतिवर्ष रुपया देना पड़ता है। अक्तूबर, नवम्बर से पैसा मांगना शुरू कर देते है। इनके यहां पत्र आया भी होगा। फाइनेंस मिनिस्टर को पैसा देना पड़ता है। सरकार क्या इस बात पर विचार करेगी कि इस तरह का व्यापार करना उचित नहीं है, अनुचित है। ये मिलें घाटे में रन कर रही है। आप हर साल किसानों का पैसा बकाया करते जा रहे हैं और इन मिलों में पैसा पम्प करते जा रहे हैं। रोज प्रेशर डालते हैं फाइनेंस मिनिस्टर पर और इनको पैसा देना पड़ता है। मैं सरकार से एक बात पूंछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि इन आठ मिलों का अधिग्रहण कर ले, ले लें नेशनालाइज्ड कर ले ? यह प्राइवेट आदमी की प्राप्ती है इसलिये इसको अच्छा कर दिया जाये, पुरानी मशीन निकाल कर नई मशीन लगा दी जाए, फाइनेंस उसमें पम्प कर दिया जाये, यह आपकी नीति है। आपको बताना चाहता हूं कि यह आपको पैसा नहीं देने वाले है। इस तरह का घाटे का व्यापार करने से अच्छा होगा कि आप इस बात पर सोचें कि इन फैक्ट्रियों को नेशनलाइज्ड कर लिया जाए ?

श्री भगवत झा आजाद : सभापति महोदय, मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि घाटे

का ऐसा व्यापार नहीं होना चाहिये । 1978 में जब कानून बना कर इन 8 फैक्ट्रियों को लिया गया, उद्देश्य प्रमुख यह रखा गया था कि उन्होंने काम नहीं किया उत्पादन का इसलिये नम्बर–एक; किसानों को राहत देने के लिये और नम्बर–दो; इनमें काम करने वाले मजदूर बेकार न हो जाएं, इसलिये ये ली गईं । हमारे दो लिमिटेड उद्देश्य थे । इन उद्देश्यों को प्राप्ति में यह कहना चाहता हूं कि हमने सारे साल बकाया रखा था । आंकड़े इस बात को कहते हैं, उदाहरण के लिये देवरिया शुगर मिल जब हमने ली थी तो 25 लाख बकाया था । इसने 1979–80 में 4 लाख का प्रोफिट दिखाया । 1980–81 में 15 लाख का प्रोफिट दिखाया और 1981–82 में 17 लाख का । अर्थात् इन्होंने इम्प्रूव किया पहले से । हमने इनको बराबर पेमेंट किया । अभी जो कठिनाई है इन आठ मिलों की वह सिर्फ इस वर्ष के लिये है जिस वर्ष का इनका बकाया हमारे ऊपर है । पिछले साल के एवरेज से अधिक नहीं है । वह इसलिये है कि पिछले वर्ष में हमको सबसे अधिक कठिनाई इसलिये पड़ी कि एग्रो क्लाइमेटिक ड्राउट था दक्षिण में और अधिक वर्षा हुई उत्तर में । इसलिये पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि हमने जब ये मिलें लीं तब से किसानों का बराबर पेमेंट किया है । इस साल का जो बकाया है उसका मैंने उल्लेख कर दिया ।

श्री सभापति : नेशनलाइज करने के बारे में क्या विचार है ?

श्री भगवत झा आजाद : दूसरी बात यह है कि इसमें अधिकांश फैक्ट्रियां ऐसी हैं, जो आपने स्वयं भी कहा कि इनकी मशीनरी बिल्कुल खत्म हो चुकी है । इनको बचाने के लिये क्या किया जाए इस पर विचार करेंगे । लेकिन नेशनलाइज करने के देश में सारी शुगर मिलें केन्द्रीय सरकार चलाये यह संभव नहीं है । प्रांतीय सरकारें चला रही है कोआपरेटिव बेसिस पर और हमने कोशिश की केशवपटन और जीजीमाता जो कोआपरेटिव है, इनको वह ले लें ।

श्री रामानन्द यादव : मान्यवर, मंत्री जी ने यह कहा कि अभी टेक-ओवर करने का विचार नहीं है, प्रान्तीय सरकारों को दे देने का विचार है । लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर प्रान्तीय सरकारें भी इन मिलों को नहीं लेना चाहती हैं तो आप इस संबंध में क्या करने का विचार रखते हैं क्योंकि प्रांतीय सरकारों ने भी लेकर किसानों का बकाया पैसा रखा है । वे बराबर पैसे को वहां पर पम्प करते जा रहे हैं । उनकी मशीनरी को रिनोवेट करने के लिये, उनको अच्छा बनाने के लिये और इस तरह से खर्चा बढ़ता चला जा रहा है । हर प्रांत ने पैसा लिया है । चाहे कोआपरेटिव फैक्ट्री हो या स्टेट की फैक्ट्री हो, उन्होंने बकाया का रुपया लिया है । इस तरह से किसान तबाह होता जा रहा है । यह कहा जाता है कि सरकार का नियन्त्रण कम रहता है बनिस्बत पूंजीपतियों के, उनका नियन्त्रण अधिक रहता है । हालांकि मैं इस पक्ष का नहीं हूं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या आप इस बात पर विचार करेंगे कि इन आठ शुगर फैक्ट्रीज को पुनः मिलों के मालिकों को दे दिया जाये और इसके लिए ऐसे नियम बनाये जाने चाहयें कि वे किसानों की बकाया की राशि का पेमेंट समय पर करते रहे ? आप इस बात को फाइन्ड आउट भी कर सकते हैं कि हर साल किसानों की बकाया की राशि उन्हें मिलती रहे । अगर वे बकाया की राशि का पेमेंट समय पर नहीं करते हैं तो जो चीनी का स्टाक होता है आप उस पर कब्जा कर सकते हैं । ऐसी स्थिति में मैं स्पष्ट रूप से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि अगर प्रांतीय सरकारें टेक-ओवर नहीं करती हैं और जैसा कि आपने बताया है कि आप सोच रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को लिखें, मैं चाहता हूं कि आप

सब को लिखें, अगर स्टेट्स गवर्नमेंटस ले लें तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं लेती हैं तो पुनः इन फैक्ट्रीज के मालिकों को लौटा दिया जाय और किसानों का बकाया का पैसा लेने के लिये कोई स्ट्रिन्जेंट कानून बनाया जाये जिससे किसानों को बकाया की राशि का भुगतान समय पर हो सके ?

श्री भगवत झा आजाद : सभापति महोदय, मैंने अपने पिछले जवाब में यह कहा था कि इन आठ मिलों में दो मिलें कोआपरेटिव सेक्टर में हैं और राज्य सरकारें कोआपरेटिव सैक्टर और सरकारी क्षेत्र में मिलें चला रही हैं। हमने प्रयत्न किया कि इन दोनों को उनको दे दें, लेकिन उन्होंने नहीं लिया । आपने सुझाव दिया है, हम यह कोशिश करेंगे कि उनसे फिर बात करें क्योंकि मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस बड़े देश में जहां अनेकानेक शुगर फैक्ट्रियां हैं, केन्द्रीय सरकार के फैक्टस भी यह कहते हैं और अनुभव भी यह कहता है कि आठ मिलों को नहीं चला सकती हैं, इनका राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकती है। इस पर आपने सुझाव दिया है कि क्या इनकों आप पुनः पुराने मालिकों को वापस करने पर विचार करेंगे, यह सजेशन फार एक्शन है ।

डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला : जहां दूसरी स्टेटों के अन्दर जो शक्कर मिल बीमार होती हैं, सिक होती हैं उनको सरकार को लेना पड़ता है या उनका राष्ट्रीयकरण करना पड़ता है, वहां महाराष्ट्र स्टेट के बारे में कितने प्रपोजल सरकार के पास आये पड़े हैं जिनमें शक्कर मिल बनाने की बात कही गई हैं... (**व्यवधान**) ।

श्री सभापति : यह तो यू०पी० का सवाल है ।

डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला : हां शक्कर पैदा होती है वह सब एक ही जोन में आता है । मेरा कहना यह है कि महाराष्ट्र के बारे में सरकार के पास जो प्रपोजल पड़े हैं उन पर सरकार निर्णय नहीं लेती है । दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि जो रिम्यूनरेटिव प्राइस दिये जाते हैं उसके लिये एक कामन पालिसी बनाई जानी चाहिये । महाराष्ट्र के अन्दर किसी डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा शक्कर पैदा होती है और किसी डिस्ट्रिक्ट में कम पैदा होती है, लेकिन सरकार की तरफ से रिम्यूनरेटिव प्राइस कामन दिये जाते हैं जबकि हिन्दुस्तान की दूसरी स्टेटों में डिफरेंट रिम्यूनरेटिव इस दिये जाते है । वहां पर कितनी शुगर उपलब्ध है उसके लिहाज से प्राइस फिक्स की जाती है । मैं यह कहना चाहती हूं कि महाराष्ट्र स्टेट के बारे में भी इसी प्रकार की पालिसी सरकार क्यों नहीं एडोप्ट करती है ?

श्री भगवत झा आजाद : सभापति महोदय, यह प्रश्न आज उन मिलों के संबंध में जो केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत हैं और इस सम्बन्ध में सारे प्रश्नों का जवाब मैं दे सकता हूं । यह जो वृहद प्रश्न माननीय सदस्या ने रखा है, इस प्रश्न के बारे में मैं इतना ही कह दूं कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा भेजे गये, यद्यपि इसका सम्बन्ध मूल प्रश्न से नहीं है, प्रस्ताव उसी रूप में विचार किया जाता है जिस रूप में और प्रांतों के सम्बन्ध में, बल्कि यह कहा जाता है, कुछ और प्रांतों की यह शिकायत है कि हमने अधिक लाइसेंस महाराष्ट्र को दिये हैं उनको कम दिये हैं । 'ईट इज अदर वे' शिकायत है । ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे विचाराधीन नहीं है । नियमों के अनुसार हम सब पर विचार करते हैं । कोई डिफरेंसिएशन महाराष्ट्र के साथ नहीं करते हैं ।

डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला : रिम्यूनरेटिव प्राइजेज का जवाब नहीं दिया गया है । जो मिलें बीमार होती हैं उसकी कोई वजह होती है । आप बराबर ग्रोवर्स को पैसा नहीं देते हैं और वे शक्कर बनाना बन्द

कर देते हैं । उनका पैसा मिलों के ऊपर पड़ा रहता है । मिल उनको दे नहीं सकते हैं । ये एक दूसरे से संबंधित प्रश्न है । मंत्री जी कहते है कि इसको उससे ताल्लुक नहीं है । ताल्लुक इस चीज से है कि जब गन्ना पैदा नहीं होगा तो मिल कैसे चलेंगी । आप अगर इसका जवाब नहीं देना चाहते तो वह दूसरी बात है ।

श्री भगवत झा आजाद : सभापति महोदय, आप ही निर्णय कर दें तो मैं जवाब दे दूंगा । यह प्रश्न सरकार के द्वारा जो आठ मिलें अभी चलाई जा रही हैं, उनके सम्बन्ध में है और यह प्रश्न सम्पूर्ण देश के केन प्राइसेज के सम्बन्ध में है ।

डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला : इनमें क्या फर्क है ।

श्री भगवत झा आजाद : आपको फर्क नहीं दिखाई पड़ता है लेकिन मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है वरना मैं जवाब दे देता ।

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव : यह क्वेश्चन इससे सम्बन्धित है ।. . .

MR. CHAIRMAN: Please do not interrupt.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: Because the prices of sugarcane...

MR. CHAIRMAN: Please do not interrupt. Otherwise, I will not allow it to be recorded I am not allowing you.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: * *

MR. CHAIRMAN: I cannot allow this kind of thing. Please remove from the record all that the honourable Member has asked. It is to be treated as unasked. Yes, Mrs. Monika Das.

**Not recorded.

SHRIMATI MONIKA DAS: Sir, I am very happy that the Government has taken eight mills. I do not know where they are taking.

MR. CHAIRMAN: They are not taking them away; they are taking them over.

SHRIMATI MONIKA DAS: Sir, the Government of Maharashtra has given nine proposals and the Government has given them the clearance. Now, the Karnataka State Government has also given some proposals relating to Bijapur, Belgaum, Dharwar, Bagalkot, etc. I would like to know whether the Government is going to accept these proposals. There is one more thing, Sir. So many sugar mills have come into existence in the country. In spite of that the price of sugar is not coming down (*Interruptions*). It has not come down. It is being sold at Rs. 6 per kg.

SHRI J. K. JAIN: No. It is only Rs. 5 per kg.

SHRIMATI MONIKA DAS: Who said that? It is only six rupees and it varies from place to place. Even in Delhi—only yesterday I had been to the market—it is being sold at Rs. 6 per kg. I would like to know why the prices are not coming down when bumper production is there in the country and whether the Government will adopt a uniform policy to see that the sugar prices come down and are the same throughout the country.

श्री भगवत झा आजाद : सभापति महोदय, विभिन्न प्रान्तों से कितनी दरख्वास्तें आईं, कितनों पर निर्णय हुआ, यह मैं नहीं बता सकता हूं और यह सम्भव भी नहीं है बताना कि हर प्रान्त से कितनी आई हैं । लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि उन पर निर्णय करने का माप-दण्ड है और वह माप-दंड हर प्रान्त के लिये एक है । एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो आपने चीनी की कीमत की बात कही यह बात सच नहीं है । जब कि दिसम्बर, 1981 में यहां पर चीनी

5 रुपये 60 पैसे से 6 रुपये 76 पैसे प्रति किलो मिलती थी, एक जुलाई को वह चीनी सारे देश में 4 रुपये 93 पैसे से 5 रुपये 25 पैसे है। मैंने यहां आने से पूर्व, मैं फिर कहूंगा, मैं झूठ बोलना नहीं चाहता या कवर अप करना नहीं चाहता, मैंने यहां आने के पहले सुपर बाजार के मैनेजर से पूछा। मैं खुद गया था तीन दिन पहले और पूछा कि आप चीनी किस रेट पर दिल्ली में बेचते हैं। दिल्ली में ज्यादा परेशानी रहती है और जगह इतनी नहीं। यहां पर चीनी 5.20 रुपये प्रति किलो ओपन बाजार में मिलती है। 65 प्रतिशत चीनी देश में लेवी में 4 रुपये किलो पर मिलती है बाकी 35 प्रतिशत है वह ओपन बाजार में जो मिलती है उसके दाम को हम नियंत्रित करते हैं रिलीज से। अभी दिल्ली में चीनी की कीमत 5.20 रुपये से 5.40 रुपये के बीच में है।

श्री सभापति : बहुत मिठास हो गई। क्वेश्चन नं० 43.

*[42.]*The questioner (Shri R. Samba Siva Rao) was absent. For answer* vide*cols* ..33. .infra].

Population Growth

*43. SHRI SANTOSH KUMAR SAHU: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there has been a rise in population despite low fertility in the country;

(b) if so, what are the details in this regard; and

(c) what are the reasons for the growth in population?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI MOHSINA KIDWAI): (a) to (c) The population in India has been rising as the decline in mortality has been steeper than the decline in birth rates.

SHRI SANTOSH KUMAR SAHU: Sir, if you see the latest figure, the Central Statistics Organisation's figures, published in May 1984, the population was 67.5 crores and the birth per anum was 33.7. In 1981 we see the population rise was also 33.9 per thousand per anum. Since the population explosion has taken gigantic proportions, has the Government of India thought of any norms or guidelines to control the population growth per the beginning of 2000 AD or by the end of the Seventh Five Year Plan?

SHRIMATI MOHSINA KIDWAI: Sir, keeping in view the national goal, a number of decisions have been taken by the Government of India. It is a very large elaborate statement. I can lay it on the Table of the House. I can assure the Member that we are taking so much interest in giving incentives. There are so many decisions which the Government of India has taken. Mr. Sahu has given figures. I can tell him that the growth rate which was showing marked increase up to 1971 has remained practically at the same level in 1981. On the basis of Sample Registration System data the birth and death rates are 33.9 and 12.5 for 1981 and 33.8 and 11.9 for 1982. The arresting of growth rate has been achieved despite a steep fall in death rate from 27.4 per thousand population in 1941—51 to 14.8 per thousand in 1971—81. It is estimated that as a result of the programme 37 million births were averted during the decade 1971—81. If these births had taken place, there would have been a growth rate of about 8 per cent instead of 2.5 per cent in the decade 1971—81. Till the end of March 1984, about 61 million births are estimated to have been averted since the inception of the programme.

SHRI SANTOSH KUMAR SAHU: Because of the enromous problem we are facing and because our population is spreading in villages will the Government consider associating the private doctors who are working in the